आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 19.04.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित, हाईस्कूल में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और हल्द्वानी के जतिन जोशी रहे अव्वल, 12वीं में देहरादून की अनुष्का राणा ने किया टॉप।
- देवबंद–रुड़की नई रेल लाइन परियोजना की 29 दशमलव पांच–पांच किलोमीटर लंबाई को मंजूरी मिली।
- चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये जिला स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
- 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में बागेश्वर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कियज़

बोर्ड परिणाम घोषित

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। हाईस्कूल में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और हल्द्वानी के जतिन जोशी ने 99 दशमलव 2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वहीं, इंटरमीडिएट में देहरादून की अनुष्का राणा ने 98 दशमलव 6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष हाईस्कूल का परिणाम 90 दशमलव 7–7 प्रतिशत, जबकि इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 83 दशमलव 2–3 प्रतिशत रहा।

रेल लाइन मंजूरी

देवबंद–रुड़की नई रेल लाइन परियोजना की 29 दशमलव पांच–पांच किलोमीटर लंबाई को रेलवे सुरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिल गई है। इस रूट पर 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस लाइन के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा का समय भी घटेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि यह परियोजना राज्य में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देगी।

## सुव्यवस्थित ग्रीष्मकालीन पर्यटन

मसूरी में ग्रीष्मकालीन पर्यटन को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में देहरादून जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में प्रशासन ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत आज से मसूरी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–163 लागू की जा रही है, जिसके तहत कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही यातायात और पार्किंग व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को स्पष्ट रुप से कहा है कि वे दिए गए निर्देशों का पूरे समर्पण के साथ अनुपालन करें और समन्वय की भावना से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को एक सुखद अनुभव देने के लिए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से यह प्रयास रहेगा कि विधिक बल के प्रयोग की आवश्यकता न पड़े और सभी व्यवस्थाएं शांतिपूर्ण रूप से संचालित हों।

मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान पार्किंग की समस्या को देखते हुए हाथीपांव, किंगक्रैग, कुठालगेट और बस्साघाट में सुरक्षित और व्यवस्थित सैटेलाइट पार्किंग विकसित की गई है। यहां से मॉल रोड तक आने–जाने के लिए हाईटेक शटल सेवाएं चलाई जाएंगी। मॉल रोड पर पर्यटकों को सुविधा देने के लिए गोल्फ कार्ट और रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मॉल रोड एंट्री गेट पर डिजिटल रिसिप्ट सिस्टम, पार्किंग स्थलों पर प्रकाश, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, शांति व्यवस्था और यातायात नियंत्रण की समुचित व्यवस्था की गई है।

श्री बंसल पूर्व में नैनीताल में भी इस प्रकार की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। अब मसूरी में भी उसी मॉडल को अपनाते हुए प्रशासन पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए कमर कस चुका है। इसके लिये यातायात पुलिस, नगर निगम, आरटीओ, पर्यटन विभाग, जल निगम और अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

## इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बढ़ोतरी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में मेक इन इंडिया पहल से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। श्री वैष्णव कहा कि पिछले इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी छह गुना वृद्धि हुई है और यह तीन लाख 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से इस समय लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन क्षमता में कई तरह के जटिल उत्पादों का निर्माण अब भारत में होने लगा है।

## डेंगू/चिकनगुनिया रोकथाम

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये जिला स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिये हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने संबंधित अधिकारियों को रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर ऐसे क्षेत्रों में काम करने को कहा जो या तो डेंगू प्रभावित हैं, या फिर जिन स्थानों में डेंगू हो सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों को डेंगू मरीजों की जानकारी आईडीएसपी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, जिसकी निगरानी संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे। निजी लैब्स को अधिकृत टेस्ट किट का ही प्रयोग करने के निर्देश देने को भी कहा गया है।

डेंगू प्रभावित जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में जन–जागरूकता अभियान तेज करने और वॉलंटियर्स की टीमें, हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल राज्य में 220 वॉलंटियर्स तैनात हैं, जिनमें सबसे अधिक देहरादून में हैं। अब तक डेंगू के 12 मामले प्रकाश में हैं, जो देहरादून के दो निजी अस्पतालों में चिन्हित हुए हैं।

## बागेश्वर प्रथम स्थान

राज्य के 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की अंतिम तिमाही के लिए जारी मूल्यांकन रिपोर्ट में बागेश्वर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर एक नई मिसाल कायम की है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अधिकारियों की सतर्कता और जनसहभागिता का परिणाम है। समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि जिलों को विभिन्न विभागों के माध्यम से हुए कार्यों की प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बागेश्वर ने कुल 126 में से 110 अंक अर्जित किए, जो 87 दशमलव 3 प्रतिशत के बराबर है। जिले ने 33 बिंदुओं पर 'A' ग्रेड प्राप्त किया, जबकि एक भी बिंदु 'D' ग्रेड में नहीं रहा। न्यूनतम मजदूरी, कृषि उत्पादकता, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बागेश्वर का प्रदर्शन विशेष रूप से उत्कृष्ट रहा। जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता की संयुक्त मेहनत और समर्पण के चलते यह मुकाम संभव हो पाया है। बागेश्वर जिले की इस उपलब्धि को पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है।

## पर्यटक सीजन नैनीताल

नैनीताल में पर्यटक सीजन के दौरान होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और पर्यटकों की सुविधा के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है, जिसका शिकायत नम्बर प्रशासन द्वारा जल्द जारी किया जाएगा। वहीं, नगर में पर्यटकों से अभद्रता और रिहायशी होटलों में मनमाफिक किराया बढ़ोतरी जैसी शिकायतों पर अलग से गठित टास्क फोर्स की नजर रहेगी।

जिलाधिकारी वंदना ने नैनीताल क्लब सभागार में पर्यटक सीजन को लेकर आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाहनों का दबाव बढ़ने पर काठगोदाम के निकट रानीबाग और गौलापार से यात्री शटल वाहनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग को ट्रायल कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कालाढूंगी मार्ग से नैनीताल को आने वाले पर्यटकों को नारायण नगर व रूसी एक से, हल्द्वानी से आने वाले पर्यटकों के लिए रूसी दो से और श्री कैंची धाम आने वाले पर्यटकों के लिए भवाली सेनेटोरियम व भीमताल से शटल सेवा संचालित की जाएगी।

मौसम

मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में आज आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी है। मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के अनुसार आज और कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी रफ्तार तीस से सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं, मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

अपर सचिव निरीक्षण

लोक निर्माण और वन विभाग के अपर सचिव विनीत कुमार की अध्यक्षता में टिहरी जिले के कीर्तिनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत बागवान ग्राम और देवप्रयाग विकासखण्ड के तुणगी में चौपाल लगाई गई। इस दौरान अपर सचिव ने ग्रामवासियों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के सम्बन्ध में वार्ता की। साथ ही योजनाओं और गांव का स्थलीय सत्यापन किया। इसके अलावा उन्होंनू जाइका प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुड़गी में निर्माणधीन ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण भी किया। चौपाल में क्षेत्रवासियों ने पेयजल, बंदर, सूअर व आवारा पशुओं की समस्या, विद्युत, सिंचाई, मनरेगा, मोटर मार्ग मुआवजा आदि की समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। अपर सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करते हुए शेष नीतिगत मामलों को शासन स्तर पर निराकरण करवाने का आश्वासन दिया।